<u>गणतंत्र पर्व २०२० - माननीय राज्यपाल जी के संबोधन</u>

गरवी गुजरात के गौरववान भाईयों और बहनों, स्वतंत्रता सेनानियों, देश-विदेश के सभी गुजरातियों और भारतवासियों को गणतंत्र पर्व की अनेक-अनेक शुभकामनाएं।

महात्मा गांधी जी ने आधुनिक भारत के लिए राम राज्य का विचार दिया था। आधुनिक समय में राम राज्य अर्थात सुशासन। गांधी जी ने कहा था कि, जब राज्य की नीतियां समाज के सबसे गरीब और कमजोर वर्ग के लिए सहायक बने तो उसे सुशासन कहा जा सकता है। गुजरात की *सबका साथ, सबका विकास* की नीति इसी सिद्धांत पर आधारित है।

आज गुजरात समग्र देश के लिए विकास का रोल मॉडल बना है। भारत के प्रधानमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दी गई विकासलक्ष्यी नीतियों और सुशासन की विरासत को प्रगतिशील गुजरात के प्रणेता मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणी दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ा रहे हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गुजरात के सपूत श्री सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा देखे गए अखंड भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए दृढ़ निष्ठा से आगे बढ़ रहे हैं। सरदार साहेब के अखंड भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए कश्मीर से अनुच्छेद ३७० हटाकर भारत को

कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक सूत्र में बांधने का कार्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कर दिया है।

विविधता वाले हमारे देश में सबको विकास के समान अवसर मिले, विकास का खुला आकाश मिले, इसके लिए संविधान निर्माता डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने ६० जितने राष्ट्रों के संविधान का अभ्यास कर हिन्दुस्तान की प्राचीन परंपरा के मुताबिक 'सभी दिशाओं से मुझे शुभ विचार प्राप्त हों' का अनुसरण करते हुए आधुनिक भारत के निर्माण के लिए एक जीवंत और पवित्र ग्रंथ संविधान हमको उपहार में दिया है। हमारा संविधान देश की मुख्य धरोहर है। देश का संविधान सबका साथ, सबका विकास मंत्र को साकार करने के लिए मार्गदर्शक बना है।

लोगों को प्रतीति हो रही है कि सरकार लगातार उनके साथ खड़ी है। गुजरात के किसान, युवा, महिलाओं, माताओं, बेटियों के लिए प्रगतिशील सरकार संवेदनापूर्ण निर्णायक कदम उठा रही है। आज के इस पावन पर्व पर गुजरात राज्य की विकास यात्रा की कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा।

असरदार प्रशासन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर पारदर्शिता, संवेदनशीलता, निर्णायकता और प्रगतिशीलता के चार स्तंभों पर मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी के नेतृत्व वाली सरकार ने गुजरात के कोने-कोने के विकास के लिए परिणामलक्ष्यी कदम उठाए हैं।

हाल ही में हुए ऑल इंडिया करप्शन सर्वे-२०१९ में २० राज्यों के २४८ जिलों के २ लाख से ज्यादा लोगों के साथ परामर्श करने के बाद जनमत प्राप्त किया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में सबसे नीची करप्शन रेट है।

मुख्यमंत्री आपत्ति में नागरिकों के साथ रहकर उनकी समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। पूर्व की सरकारें राज्य में अकाल की घोषणा जनवरी माह में किया करती थीं। जबकि संवेदनशील श्री विजयभाई रूपाणी की सरकार ने वर्ष २०१८-१९ में अक्टूबर माह में ही अकालग्रस्त क्षेत्रों की घोषणा कर दी थी। किसानों के प्रति संवेदनशीलता दर्शायी है। पिछले तीन वर्ष में बेमौसम बरसात ने किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया था तब भी यह सरकार किसानों की हितैषी बनकर उनके साथ खड़ी रही। चालू वर्ष में भी प्रभावित किसानों को ३७९५करोड़रुपए का पैकेज इस सरकार ने दिया है। राज्य में पिछले तीन वर्ष से अकाल के लक्षण दिखाई देते थे। उस वक्त राज्य सरकार ने सुजलाम सुफलाम योजना द्वारा राज्य में पेयजल और सिंचाई के पानी की तकलीफ दूर करके उसके स्थायी निराकरण के लिए दीर्घकालिक कदम उठाए। इस योजना को दो चरणों में लागू करके जल संचय का उत्तम कार्य किया गया है। राज्य में बढ़ रही क्षारित जमीन, नीचे जा रहे जल स्तर तथा समुद्र में बह जाने वाले पानी को रोककर राज्य में जल संग्रह की शक्ति को बढ़ाया है।

नीति आयोग द्वारा वर्ष २०१८-१९ के लिए प्रकाशित किए गए कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स में गुजरात प्रथम क्रमांक पर रहा है। प्रधानमंत्री की नल से जल योजना के अंतर्गत वर्ष २०२२ तक सौ प्रतिशत लक्ष्यांक सिद्धि के वर्ष २०२२ से एक वर्ष पूर्व २०२१ तक इसे हासिल करने के लिए गुजरात ने कमर कसी है।

मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि राज्य में नागरिकों को १८ जितने सरकारी दस्तावेजों और ५७ से ज्यादा सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार सेवा सेतु कार्यक्रम के अंतर्गत नागरिकों के घर तक पहुंची है। इसका लाभ १ करोड़ ५३ लाख जितने नागरिकों को मिला है।

सामान्यतया जिस राज्य में औद्योगिक विकास दर ऊंची होती है उस राज्य में कृषि दर नीची होती है। अथवा तो जिस राज्य में कृषि दर ऊंची होती है उस राज्य में औद्योगिक विकास की दर नीची होती है। परन्तु गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां उद्योग, कृषि और सेवा इन तीनों विभागों की विकासलक्ष्यी परिभाषा संतुलित रही है। यहां विकासलक्ष्यी, सेवालक्ष्यी और उद्योगलक्ष्यी सुधारों और कानूनों को अमल में लाया गया है। आई-औरा की अप्रतिम सफलता के बाद नागरिकों को सरलता से योजनागत लाभ मिले और पारदर्शितापूर्वक उनको उनके अधिकार जल्द मिलें, इस दिशा में आई-औरा एक महत्वपूर्ण कदम है। आई-औरा सौ प्रतिशत फेसलेस सिस्टम है जिसके कारण राजस्व लाभ नागरिकों की

उंगली के इशारे पर उपलब्ध होने लगे हैं। राज्य में कृषि, उद्योग और सेवा सहित तीनों क्षेत्रों का विकास रॉकेट की गति से आगे बढ़ रहा है।

कई लोगों द्वारा समाज में असमानता और वैमनस्य फैलाने का षड़यंत्र चल रहा है, ऐसे में विद्यार्थीकाल से ही नागरिकों में सामाजिक समरसता के गुण शामिल हो जाएं, इसके लिए राज्य के विभिन्न शहरों और जिलों में आधुनिक सुविधाओं के साथ १८ जितने स्वामी विवेकानंद समरस छात्रालय बनाए जा रहे हैं। दिव्यांगों को आर्थिक और सामाजिक तथा शैक्षणिक, तमाम क्षेत्रों में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं अमल में हैं जिनके कारण गुजरात के दिव्यांग आज पैरा ओलम्पिक, सार्वजनिक इकाईयों और सरकारी क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

यह सरकार युवाओं की है, यह कहते हुए मुझे गर्व हो रहा है। पिछले तीन वर्ष में डेढ़ लाख से ज्यादा युवाओं को अप्रेंटिस योजना के अंतर्गत रोजगार-स्वरोजगार उपलब्ध करवाया गया है। रोजगार भर्ती मेले के नवीनतम अभिगम द्वारा सरकार ने अब तक १५ लाख युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए हैं। करीब ३ लाख जितने विद्यार्थियों को १००० रुपए के मामूली मूल्य पर टैबलेट्स उपलब्ध करवाए गए हैं। चिकित्सा क्षेत्र में राज्य के विद्यार्थियों को राज्य के बाहर न जाना पड़े, इसके लिए इस संवेदनशील सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र में बैठकें दोगुनी कर दी है और अब ५५०० से ज्यादा सीटें उपलब्ध हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के डिजीटल इंडिया के स्वप्न को साकार करते हुए रूर्बन के अंतर्गत ग्राम्य क्षेत्र से ही महत्वपूर्ण सेवाएं और अनेक प्रकार के प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। बिचौलियों को दूर करके किसी भी सरकारी योजना का लाभ सीधा लाभार्थी को ही मिले इसके लिए वर्ष २०१८-१९ में १५३० गरीब कल्याण मेलों का आयोजन करके करीब डेढ़ करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को साधन-सहायता का लाभ प्रदान किया गया है।

रोजगार और अभ्यास के लिए सुदूरवर्ती गांवों और कस्बों में से लोग शहर की ओर आ रहे हैं। स्थानांतरण करने वाले लोगों और स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य, परिवहन और मनोरंजन की तमाम सुविधाएं उपलब्ध हों, इसके लिए राज्य सरकार ने अर्बन हेल्थ सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वेंडर मार्केट, हॉकर्स जोन, पार्किंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, फ्लाईओवर, मेट्रो, बीआरटीएस, एम्यूजमेंट पार्क, रिवरफ्रंट तथा बाग-बगीचों की सुविधाएं उपलब्ध करवाई है। गुजरात में करीब ४५ प्रतिशत नागरिक शहरों में बसे हुए हैं। आधुनिक और विकसित शहर गुजरात की अनोखी पहचान बन गए हैं। विशाल सड़कें, पीने का शुद्ध पानी, भूगर्भ गटर व्यवस्था, गरीब क्षेत्रों में अंतर्ढांचागत सुविधाओं के साथ बाग-बगीचे और फ्लाईओवर आदि सुविधाओं के साथ गुजरात के शहर स्मार्ट बन रहे हैं। गुजरात सरकार ने राज्य के तमाम शहरों को सुविधायुक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं।

जिस राज्य में बिजली उपयोग दर ऊंची होती है उस राज्य की जीवन शैली और उद्योगों की ऊंची विकास दर बतलाती है। परन्तु बिजली उपयोग के कारण बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए गुजरात सरकार ने ग्रीन एनर्जी-क्लीन एनर्जी के मंत्र को अपनाया है। शहरों और ग्रामीण स्तर पर एलईडी बल्ब, सुएज ट्रीटमेंट प्लांट, सोलर पावर प्लांट और हाइड्रो पावर स्टेशन आदि कार्यरत किए हैं।

उद्योग राज्य की आर्थिक विकास की जीवनरेखा है। राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ रहे हैं। सरकार ने पिछले पांच वर्षों में कई महत्वपूर्ण नीति विषयक निर्णय लिए हैं। इनके कारण औद्योगिक शांति और समरसता बरकरार रही है और व्यापार के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में गुजरात अग्रसर है। मजबूत मनोबल और पारदर्शी नीतियों के कारण गुजरात के सर्वांगीण विकास में औद्योगिक विकास का योगदान महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मेक इन इंडिया स्वप्न को साकार करने के लिए स्टूडेंट स्टार्टअप Open Innovation Policy घोषित की गई है। भारत सरकार के DI&PP द्वारा State Start-up Ranking Framework - २०१८ के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में गुजरात को स्थान दिया गया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी एलईडीएस इंडेक्स-२०१९ के मुताबिक देश में लॉजिस्टिक सेक्टर में गुजरात उच्च रैंकिंग वाला राज्य है। कुदरती सौंदर्य के साथ-साथ राज्य सरकार ने देश

के लौहपुरुष, एकता और अखंडता के शिल्पी सरदार पटेल के विश्व के विशालतम और ऊंचे कद के स्मारक का केवड़िया में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाकर पर्यटकों को आकर्षित किया है। जबकि दूसरी ओर डायनासोर के जीवाश्मो को विश्व के समक्ष रखने के लिए महीसागर जिले के बालासिनोर में विश्व का तीसरा और भारत का प्रथम फॉसिल पार्क बनाकर विश्व के पर्यटकों को गुजरात घूमने के लिए प्रोत्साहित किया है। गुजरात में आने वाले पर्यटकों की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में दोगुनी हुई है।

देश-विदेश के उद्योगपतियों के निवेश के लिए गुजरात पहली पसंद बना है। गुजरात मैन्यूफेक्चरिंग और ऑटोमोबाइल हब के साथ दूसरे अन्य इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में भी अग्रसर बन रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगामी समय में गुजरात हॉलिस्टिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का रोल मॉडल बनेगा।

जल और जमीन दिनोंदिन ज्यादा प्रदूषित हो रहे हैं। किसान ज्यादा फसल लेने के लिए रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं। जिसके कारण खेती की जमीन अपनी उत्पादकता खो रही है। ऐसे समय में गुजरात की संवेदनशील सरकार किसानों को जैविक खेती की ओर ले जाने तथा सेन्द्रिय खाद द्वारा ज्यादा उत्पादन हासिल करने के लिए कार्यशाला चला रही है। इस प्रयास के अंतर्गत सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि तालीम कार्यशाला के अंतर्गत २२,९७४ किसानों को प्राकृतिक खेती

विषयक तालीम दी गई है। राज्य में २०१७ से २०२२ तक डांग जिला संपूर्ण, वलसाड़ जिले की धरमपुर और कपराड़ा, नवसारी जिले की वांसदा तहसील को १०० प्रतिशत सेंन्द्रिय खेती के तहत शामिल कर लेने के सघन प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले कई वर्षों में कभी अकाल तो कभी अतिवृष्टि का शिकार गुजरात बना है। इसके बावजूद गुजरात सरकार के प्रोत्साहन और किसानों की मेहतन-दक्षता के कारण पांच जितने राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार गुजरात के किसानों ने जीते हैं।

किसानों की वर्ष २०२२ तक आय दोगुनी करने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन और मिशन के लिए राज्य सरकार ने अनेक परिणामलक्ष्यी कदम उठाए हैं। विभिन्न योजनाओं का लाभ राज्य के किसानों को आसानी से मिले और पारदर्शिता बनी रहे, इस उद्देश्य से तमाम योजनाओं का अमलीकरण आई-खेड़ुत पोर्टल पर हो रहा है। ई-नाम योजना द्वारा राज्य की ७९ बाजार समितियों को जोड़ा गया है। इस पोर्टल पर कृषि, किसान सहायता और अन्य योजनाओं की जानकारी रखी गई है जिसके कारण अब किसानों को मिलने वाले लाभ सीधे उनके बैंक खातों में जमा होते हैं।

जीव मात्र के प्रति करुणा रखने वाली गुजरात सरकार ने मूक पशु-पक्षियों के लिए राज्य में ३७ जितनी करुणा एनीमल एंबुलेंस- १९६२ कार्यरत की है। पिछले तीन वर्ष में ४०,००० से ज्यादा मूक पशु-पक्षियों का उपचार किया गया है।

गुजरात के खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने राज्य और राष्ट्र का नाम रोशन करें, इस उद्देश्य से इस वर्ष खेल महाकुंभ के अंतर्गत पांच जितनी ओलंपिक मान्य टीमों-खेलों का समावेश किया गया है।

महिलाओं का सम्मान, उनकी सुरक्षा और सशक्तिकरण गुजरात की प्राथमिकता रही है। गुजरात ने इस दिशा में अनेक आयोजन करके, योजनाओं का आरंभ करके और कदम उठाकर सही अर्थों में नारी को सशक्त बनाया है। स्टेट मैनेजमेंट सेंटर महिलाओं और बालकों को शिक्षा की सुविधाओं से संबंधित तमाम रियल टाइम जानकारी उपलब्ध करवाता है। ५५,००० से भी ज्यादा कार्यकर्ताओं द्वारा ३.६ मिलियन बालकों को यह सुविधा प्रदान की जाती है। देश की गरीब, मध्यम वर्ग की महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा तथा महिला सशक्तिकरण का विषय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्राथमिकता रहा है। व्हाली दीकरी योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, पूर्णा योजना, जेंडर बजट, १८१ अभयम हेल्पलाइन एप, नारी अदालत, चिरंजीवी योजना, किशोरियों को पोषण और प्रशिक्षण, जननी सुरक्षा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तथा आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण द्वारा राज्य की विकास यात्रा में उनका योगदान सुनिश्चित करने का भगीरथ कार्य इस सरकार ने किया है।

जब नीयत साफ हो तब कुदरत भी साथ देती है। पिछले दो दशक से विकास को समर्पित सरकार को कुदरत का आशीर्वाद भी मिला है

जिसका उत्कृष्ट उदाहरण है नर्मदा डैम का छलकना। तारीख १५-०९-२०१९ को नर्मदा डैम १३८.६८ मीटर के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया और गुजरातियों का दशकों पुराना स्वप्न साकार हुआ है।

गुजरात अब उद्‌योग, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में अग्रसर है। इस प्रगति का कारण सरकार का सुशासन और नागरिकों का सामूहिक प्रयास है। कभी अनावृष्टि तो कभी अतिवृष्टि के सामने अडिग खड़ा रहने वाला गुजरात अब विकास के रनवे पर है। आकाश छूती विकास की ऊंचाइयों को पार करने के लिए प्रतिबद्‌ध बने, इस संकल्प के साथ सभी गुजराती बंधुओं को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।

जय हिंद

जय-जय गरवी गुजरात...

****